

एनसीआर के साथ बुंदेलखंड में भी बनेगा डाटा सेंटर क्लस्टर : सीएम

योगी ने डाटा सेंटर क्लस्टर, प्रोजेक्ट गंगा और गेहूं प्रसंस्करण नीति की समीक्षा की

अमर उजाला ब्यूरो

10 हजार युवा बनेंगे डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर क्लस्टर, प्रोजेक्ट गंगा तथा गेहूं के इन-हाउस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने संबंधी प्रस्तावों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि यूपी डाटा सेंटर क्लस्टर केवल एनसीआर तक सीमित न रहे, बल्कि इसकी शुरुआत बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) क्षेत्र से भी की जाए, जहां बड़े पैमाने पर भूमि उपलब्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि डाटा सेंटर क्लस्टर प्रदेश के एआई मिशन की बुनियादी संरचना तैयार करेगा। बैठक में बताया गया कि वर्ष 2040 तक यूपी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, साइबर सिक्योरिटी, रोबोटिक्स, सेमीकंडक्टर और हाई-टेक डिजिटल मैनुफैक्चरिंग का वैश्विक केंद्र बनाने का लक्ष्य है। इसके तहत 5 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था, 1.5 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार और 5 गीगावॉट एआई कंप्यूट कौरिडोर विकसित करने की योजना है।



प्रोजेक्ट गंगा की समीक्षा के दौरान सीएम ने चयनित युवाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने के निर्देश दिए। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड नेटवर्क पहुंचाया जाएगा। सरकार 10 हजार युवाओं को डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर (डीएसपी) के रूप में तैयार करेगी, जिससे 50 हजार प्रत्यक्ष और एक लाख से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार

सृजित होने का अनुमान है। प्रत्येक डीएसपी 200 से 300 घरों को इंटरनेट सेवा से जोड़ेगा। योजना के तहत 20 लाख घरों को फाइबर आधारित इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक डीएसपी को पांच लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण भी मिलेगा।

खाद्यान्न भंडार मजबूत करने के निर्देश : सीएम ने गेहूं के इनहाउस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने, मंडी शुल्क व्यवस्था में सुधार और मंडियों को आधुनिक व स्वच्छ बनाने पर भी जोर दिया। अल नीनो के संभावित प्रभाव को देखते हुए उन्होंने राज्य के खाद्यान्न भंडार पर्याप्त और मजबूत रखने के निर्देश दिए।

स्टंटबाजी और नशे में ड्राइविंग पर करें सख्त कार्रवाई

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि स्टंटबाजी, ओवरस्पीड और नशे में वाहन चलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। बुधवार को आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि सड़क हादसों में होने वाली मौतें राज्य और देश दोनों के लिए बड़ी क्षति हैं। उन्होंने अधिकारियों को सड़क पर उतरकर वास्तविक स्थिति परखने और हादसे रोकने के प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने लखीमपुर खीरी, अमरोहा, आगरा और अलीगढ़ में हाल की दुर्घटनाओं पर चिंता जताई। उन्होंने हेलमेट, सीट बेल्ट और यातायात नियमों के पालन के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाने, ब्लैक स्पॉट सुधारने, ओवरलोडिंग, डगमगार बसों व अवैध डंपरों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। बार-बार चालान होने पर लाइसेंस व परमिट निरस्त करने को भी कहा। बसों और स्कूल वाहनों की फिटनेस व चालकों की स्वास्थ्य जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जनवरी से अप्रैल 2026 के बीच सड़क हादसों में 21% और मृतकों की संख्या में 22% कमी दर्ज की गई। ब्यूरो